भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4234
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

प्रौद्योगिकी में भारी बदलाव

4234. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर हो रहे प्रौद्योगिकी में भारी बदलाव के बारे में पता है, जिससे कार्यबल की बड़ी आबादी रोजगार के लिए अयोग्य हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विशेषकर सीमांत सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यबल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग को अपनाकर तकनीकी बदलाव के अनुसार फिट होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरी चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र में कामकाजी आयु समूहों के कौशल में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 52.9% हो गया है।

सरकार का यह मत है कि हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और नौकरियों के विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) गतिज सक्षम होनी चाहिए। एआई पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और युवाओं को एआई के अवसरों से जोड़ने के लिए, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के हाशिए वाले व्यक्ति शामिल हैं, सरकार ने देश में विभिन्न निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i) सरकार ने एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 'विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना' शुरू की है।

ii) मेटी (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुन: कौशल/कौशल उन्नयन के लिए 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

iii) एआई के लिए तैयार होने के साथ-साथ, कुशल एआई युवाओं को बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर सरकारी स्कूल के बच्चों, जिनकी नवीनतम तकनीकों और संसाधनों तक पहुंच सीमित थी या बिलकुल नहीं थी, उनके बीच एआई जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई' कार्यक्रम शुरू किया है।

iv) सरकार ने इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) भी लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआईएच) बनाया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और टेक्नोक्रेटों को बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के द्वारा और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) माड्यूल को 1 वर्ष की अवधि के इंटरनेट ऑफ थिंग्स- स्मार्ट हेल्थकेयर (आईओटी-स्मार्ट हेल्थकेयर) के एक कोर्स के तहत कवर किया गया है। वर्तमान में, देश में कुल 14,953 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 501 तमिलनाडु में हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), सितंबर, 2014 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में 12 हजार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईज), कौशल और उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। 18-45 वर्ष की आयु का कोई भी बेरोजगार युवा, जो स्वरोजगार या वेतन रोजगार लेने की योग्यता रखता हो और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखता हो, वह आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तमिलनाडु में वर्ष 2022-23 में (फरवरी, 2023 तक) 24 हजार उम्मीदरवारों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस मंत्रालय का राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल अपने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को करियर"कौशलपर " एक मुफ्त, स्वकेंद्रित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है-, जो नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उक्त कार्यक्रम के तहत चेन्नई में 292 नौकरी चाहने वालों को प्रमाणित किया गया है।

इन सभी पहलों से कौशल में सुधार होने और इनके गुणक-प्रभावों के माध्यम से, मध्यम से दीर्घावधि में, सामूहिक रूप से रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

*****